भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4315

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

महानंदा नदी का पुनरुद्धार

4315. श्री राजू बिष्ट:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घोर अनदेखी के कारण सिलीगुड़ी की जीवनरेखा महानंदा नदी सूख रही है और इसके लिए नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर तत्काल नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कलिमपोंग, कुरसियांग तथा मिरिक शहर और मटिगारा और फांसीदेश के पूरे क्षेत्र वर्ष 2008 से पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाना प्रस्तावित हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2016 और 17 में जल गुणवत्ता निगरानी के आधार पर पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी से बिनागुड़ी तक महानंदा नदी के एक क्षेत्र सहित देश में 351 नदी क्षेत्रों की पहचान प्रदूषित क्षेत्र के रूप में की गई है। देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान तथा प्राथमिकीकरण के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग स्तर के मानदंड पर विचार किया जाता है। महानंदा नदी को प्राथमिक श्रेणी-।। अर्थात् 20-30 मि.ग्रा./ली. के रेंज में बीओडी मान के तहत वर्गीकृत किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महानंदा नदी के प्रदूषित क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की है। जिसे सीपीसीबी कार्यबल द्वारा अनुमोदित किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को ओए संख्या 673/2018 में दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 और 08.04.2019 के माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना में दो वर्षों (01 अप्रैल, 2019 से) के भीतर इसका निष्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) जलापूर्ति, राज्य का विषय है भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है। भारत सरकार ने मिशन वाले शहरों में बुनियादी शहरी अवसंरचना विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पांच वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक देश भर में 500 शहरों में 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है। अमृत मिशन के तहत प्राथमिक क्षेत्रों में से एक जलापूर्ति है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और सिलिगुड़ी अमृत शहर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग में 204.84 करोड़ रूपए की राशि सहित जलापूर्ति की एक परियोजना शुरू की है, जिसके लिए संविदा दे दी गई है।

****